

## उत्तराखण्ड में समान नागरिक संहिता नयिम

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखण्ड सरकार ने **समान नागरिक संहिता (UCC)** के नयिमों को मंजूरी दे दी है और **जनवरी 2025** के अंत तक कानून के लिये राजपत्र अधिसूचना जारी करने की योजना है, जिससे इसके कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त होगा।

### मुख्य बटु

- **UCC के प्रमुख प्रावधान:**
  - फरवरी 2024 में उत्तराखण्ड वधिनसभा द्वारा पारित समान नागरिक संहिता (UCC) आदविसी समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखती है।
  - यह हलाला, इद्दत और तलाक जैसी प्रथाओं पर प्रतबंध लगाता है, जो **मुसलमि परसनल लॉ** के तहत प्रथाएँ हैं।
    - यह सुनश्चित करता है कि महिलाओं को संपत्त और उत्तराधिकार के मामलों में **समान अधिकार प्राप्त हों**।
  - संहिता में **वविाह और तलाक के पंजीकरण को अनविर्य बनाया गया है**, जिसका अनुपालन न करने पर सरकारी लाभों से वंचति होना पड़ेगा।
  - **अपंजीकृत लवि-इन संबंधों** के लिये कड़े प्रावधान मौजूद हैं, हालाँकि ऐसे संबंधों से पैदा हुए बच्चों को वैध माना जाता है।
- **कार्यान्वयन उपाय:**
  - सरकार ने वविाह, तलाक, उत्तराधिकार अधिकार, लवि-इन रलेशनशिप और लवि-इन रलेशनशिप की समाप्त के पंजीकरण के लिये एक ऑनलाइन पोर्टल स्थापति कया है।
  - नागरिक अपने डेटा और आवेदन की स्थतिको मोबाइल फोन या घर से देख सकते हैं।
  - **सामान्य सेवा केंद्रों (CSC)** को ऑनलाइन पंजीकरण के लिये अधिकृत कया गया है।
    - इंटरनेट सुवधि से वंचति दूरदराज के क्षेत्रों में CSC एजेंट घर-घर जाकर पंजीकरण सेवाएँ प्रदान करेंगे।
  - सरलता और सुवधि के लिये ईमेल और एसएमएस के माध्यम से **आधार-आधारति पंजीकरण** और ट्रैकगि की शुरुआत की गई है।
  - ऑनलाइन शकियात पंजीकरण तंत्र भी स्थापति कया गया है।



# UNIFORM CIVIL CODE

All sections of the society irrespective of their religion shall be treated equally according to a National Civil Code - the Uniform Civil Code.

## THEY COVER AREAS LIKE



Marriage



Divorce



Maintenance



Inheritance



Adoption



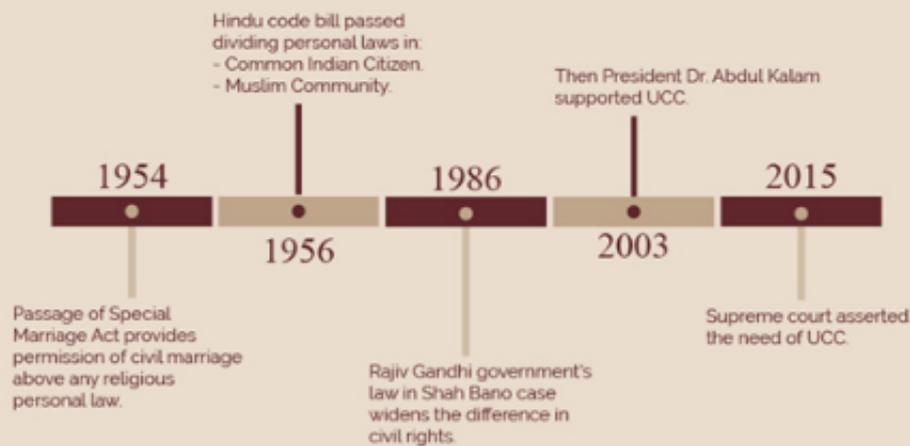
Succession of Property

It is based on the premise that there is necessarily no connection between religion and personal law in a civilized society.

**"UCC refers to a common set of laws governing civil rights of every citizen."**

**Article 44 of Directive Principles sets duty of state for implementing UCC.**

## TIMELINE



The dialogue for UCC was started by the Law Commission in the year 2016